50 तरह के टेस्ट और 116 तरह की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराएगी हिमाचल प्रदेश सरकार। इसके लिए जीवन धारा योजना जल्द शुरू करने की तैयारी है। योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराई जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 30 जुलाई 2019

मप्र के श्योपुर में 127 पटवारी एक साल से बिना काम के पा रहे वेतन

हरिओम गौड़, श्योपुर

श्योपुर में पटवारियों के कुल 233 पद, भर्ती हो गए 360 पटवारी

भर्ती के समय पटवारी हल्कों की गलत गणना कर ली गई, इसलिए 127 पटवारी ज्यादा हो गए। हमारे यहां इनके लिए पद रिक्त नहीं है, इसलिए आयुक्त भू-अभिलेख को पत्र लिखकर इन 127 पटवारियों को दूसरे जिलों में पदस्थ करने के लिए पत्र लिखा है।
-बसंत कुर्रे, कलेक्टर श्योपुर

अब इन्हें अन्य जिलों में पदस्थ करने के लिए दम लगा रहे अफसर

श्योपुर जिले में 127 ज्यादा पटवारी भर्ती कर लिए गए हैं। श्योपुर कलेक्टर ने इन पटवारियों को वापस विभाग में लेकर अन्यत्र जिलों में पदस्थ करने के लिए पत्र भेजा है।
- ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मप्र

मप्र के श्योपुर जिले में राजस्व विभाग ने जरूरत से ज्यादा पटवारियों की भर्ती कर डाली। श्योपुर में दस-बीस नहीं, बल्कि 127 पटवारी ज्यादा भर्ती हो गए हैं। नतीजा बीते एक साल से यह पटवारी बिना काम के वेतन पा रहे हैं।

राजस्व विभाग ने जुलाई 2017 में पूरे प्रदेश में 7,398 पदों पर पटवारियों की भर्ती निकाली थी। तब मप्र सरकार ने हर जिले से पटवारियों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, उसी के आधार पर जनवरी-फरवरी 2018 में परीक्षा के बाद पटवारियों की भर्ती भी हो गई। इस भर्ती परीक्षा के बाद श्योपुर में 184 पटवारी भर्ती किए गए। जिले में पूर्व से ही 176 पटवारी पदस्थ थे। नई भर्ती के बाद जिले में पटवारियों की संख्या 360 हो गई, जबकि जिले में पटवारियों के पद 233 ही हैं। बचे हुए 127 पटवारी ऐसे हैं, जिनके लिए एक साल से कोई हलका नहीं मिल रहा। नतीजा अगस्त 2018 से यह पटवारी हर महीने बिना काम के वेतन पा रहे हैं। श्योपुर कलेक्टर इन 127 पटवारियों को दूसरे जिलों में भेजने के लिए मप्र लैंड रिकॉर्ड के कमिश्नर को कई पत्र भेज चुके हैं।

इसलिए हो गई गफलत : पटवारी हलके ग्राम पंचायतों के हिसाब से रहते हैं। श्योपुर में 225 ग्राम पंचायतें हैं जिनके लिए 225 पटवारी चाहिए। इनके अलावा श्योपुर, विजयपुर और बड़ौदा शहरी क्षेत्र में तीन और तहसीलों में वर्कलोड पटवारी के पांच पद है। यानी कुल मिलाकर 233 पटवारी जिले में चाहिए, लेकिन 2017 में तत्कालीन कलेक्टर और एसडीएम ने पटवारी हल्कों की गणना गलत कर दी। एक पंचायत में दो से तीन-तीन हलके बनाकर 352 पद बना दिए, जो नियम विरुद्ध थे। हलकों की गलत गणना के कारण 127 पटवारी ज्यादा भर्ती हो गए।

भर्ती से पहले ही नईदुनिया ने चेताया, तब भी नहीं सुनी : जुलाई 2017 में जब मप्र सरकार ने 7,398 पटवारियों की भर्ती की विज्ञप्ति निकाली थी तभी नईदुनिया ने बताया था कि श्योपुर जिले में पदों से ज्यादा पटवारियों की भर्ती की जा रही है। पूर्व के अफसरों की यह लापरवाही अब वर्तमान कलेक्टर, एसएलआर से लेकर एसडीएम व तहसीलदारों के लिए सिरदर्द बन चुकी है।

गोवा कैबिनेट बैठक में मंत्री ने दी थी मुझे गाली : धवलीकर

पणजी, प्रेट्र : गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री व महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदीन धवलीकर ने सोमवार को विधानसभा में आरोप लगाया कि इस साल जनवरी में कैबिनेट बैठक के दौरान तत्कालीन संस्कृति मंत्री गोविंद गावड़े ने दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर के समक्ष उनके लिए असंसदीय व अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उन्हें गालियां दी गई थीं। इसके बाद वह सदन से बाहर भी चले गए। धवलीकर ने यह मामला ऐसे समय उठाया है जब लोकसभा में अध्यक्ष के आसन पर विराजमान रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सपा सांसद आजम खां को सोमवार को सदन में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी।

एमजीपी विधायक ने कहा कि संसद और विधानसभा की गरिमा बनी रहनी चाहिए। आजम की टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब गावड़े ने उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था तब मौवीन गोडिन्हो और विश्वजीत राणे वहां मौजूद थे। विधानसभा को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को इसकी जांच करानी चाहिए। गावड़े ने धवलीकर के आरोपों को झूठा करार दिया, जबकि मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि जब मामला हुआ था, तभी शिकायत करनी चाहिए थी।

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के लिए हो रही नए फार्मूले की तलाश

नईदुनिया, रायपुर

15 सितंबर को खत्म हो रहा है रेलिगेयर बीमा कंपनी के साथ राज्य सरकार का अनुबंध, नई कवायद में सरकार

मौजूदा टेंडर की प्रीमियर दर

1100 रुपये : प्रति परिवार प्रीमियर की राशि

62.17 लाख : स्मार्ट कार्ड योजना के तहत है दर्ज परिवारों की संख्या

772 बीमारियों का योजना के तहत हो रहा है इलाज

350 करोड़ रुपये हो रहा है सालाना बीमा कंपनी को भुगतान

आयुष्मान योजना के तहत कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जिनका इलाज बगैर पैकेज में सम्मिलित किए हुए भी सरकारी अस्पताल में हो सकता है। अगस्त तक इसकी स्क्रूटनिंग करके आगे की प्रक्रिया की जानी है।
- विजेंद्र कटरे, एडिशनल सीइओ, आयुष्मान भारत एवं एमएसबीवाइ

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाइ) के तहत अनुबंधित बीमा कंपनी रेलिगेयर से राज्य सरकार का अनबुंध सितंबर में खत्म होने जा रहा है। इसके पहले सरकार रायशुमारी की कवायद में जुट गई है। योजना की कमियों, खामियों को जानने से लेकर बीमारियों के पैकेज जोड़ने-घटाने और अन्य सुझावों को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव संभागवार बैठकें कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री बैठक की शुरुआत 24 जुलाई को अंबिकापुर कर चुके हैं। इसमें सरकारी, गैर सरकारी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) और हॉस्पिटल बोर्ड के तहत डॉक्टर्स सदस्यों से मशवरा किया जा रहा है। रायपुर में 26 अगस्त को बैठक प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक सरकार योजनाओं के संचालन के लिए समिति (सोसाइटी) भी बना सकती है? इसे लेकर सरकार के स्तर पर मंथन जारी है। अगर ऐसा होता है तो बीमा कंपनी की जरूरत नहीं होगी। मगर सोसाइटी का सेटअप खड़ा करना बड़ी चुनौती है। अगर सोसाइटी नहीं बनती है तो फिर मौजूदा बीमा कंपनी से अनुबंध की व्यवस्था ही चलेगी।

पैकेज में कटौती की भी तैयारी : वहीं, दूसरी तरफ इन योजना के तहत बीमारियों के पैकेज में भारी कटौती करने की तैयारी में है। ऐसी बीमारियां, जिनके इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा। इससे प्रीमियम की राशि, जो अभी 1100 रुपये प्रति परिवार है, उसमें कमी आएगी। 'नईदुनिया' को उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार नहीं चाहती है कि योजनाओं में निजी अस्पतालों की अधिक भागीदारी हो। यही कारण है कि आयुष्मान योजना के समानांतर ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर को स्थापित किया जा रहा है।

...तो क्या समानांतर कांग्रेस चलाएंगे हुड्डा

तैयारी ▶ अपने राजनीतिक गढ़ रोहतक में परिवर्तन महारैली दिखाएंगे दमखम

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल फोटो

रोहतक पर ही फोकस के हैं कई कारण

भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव में जीत के बावजूद अपनी बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के लिए रोहतक में ही फोकस किया है। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दो दिन का प्रवास तो हाल ही में रोहतक में हुआ है। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह भी 16 अगस्त को रोहतक से सटे जींद में आएंगे है। असल में भाजपा मानती है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक और सोनीपत में अब सेंध लग चुकी है। भाजपा की इस रणनीति के चलते ही हुड्डा ने भी अपनी रैली रोहतक में रखी है।

हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान की सहमति से राज्य के 15 शीर्ष नेताओं की समन्वय समिति को प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खारिज कर दिया है। खुद हुड्डा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव से पूर्व बनी समन्वय समिति को सबसे पहले तंवर ने दरकिनार किया था। उन्होंने समिति या पार्टी हाईकमान की सहमति के बिना ही विधानसभा चुनाव योजना एवं प्रबंधन कमेटी बना दी। हालांकि बाद में तंवर ने इस कमेटी को समूह का नाम दिया क्योंकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कमेटी को पार्टी लाइन के खिलाफ बताया था।

अब हुड्डा ने भी समन्वय समिति की बैठक किए बिना अपने समर्थक विधायकों के बीच ही 18 अगस्त को रोहतक में परिवर्तन महारैली का एलान कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि हुड्डा ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बावजूद राज्य कांग्रेस संगठन के बदलाव में हाईकमान की तरफ से हो रही देरी कारण यह निर्णय लिया है। इस निर्णय से हुड्डा एक तीर से दो निशाने साधने की जुगत में है। एक तो बार-बार कानूनी शिकंजा कसे जाने से नाराज हुड्डा सत्तारूढ़ दल भाजपा को अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं, दूसरी अपने ही दल में हाईकमान को जमीनी हकीकत से परिचय कराएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हुड्डा समानांतर कांग्रेस चलाएंगे, क्योंकि रविवार को नई दिल्ली स्थित 9 पंत मार्ग पर जब रोहतक महारैली की परिकल्पना की जा रही थी तो इसमें उपस्थित उनके समर्थक विधायकों ने हुड्डा से यहां तक कहा था कि वे आर-पार की लड़ाई लड़ें।

भाजपा से भी पहले कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत का अहसास कराना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा के तमाम दबाव के बावजूद भी तंवर को नहीं हटाया। हुड्डा समर्थक विधायक खुलेआम यह कह रहे हैं कि अब तंवर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने पांच साल से भी ज्यादा समय हो गया है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की यह दुर्गति इसलिए हुई कि पिछले पांच साल से राज्य में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संगठन नहीं है।

कांग्रेस के लिए आसान नहीं हुड्डा की अनदेखी: हुड्डा पहली बार राज्य में प्रदेशाध्यक्ष के बिना रैली नहीं कर रहे हैं। 2018 में भी उन्होंने जनक्रांति रथयात्रा का होडल से श्रीगणेश किया था और इस यात्रा में उमड़ी भीड़ के बावजूद पार्टी हाईकमान ने हुड्डा को उनके मनमाफिक पद नहीं दिया। समय-समय पर हुड्डा पार्टी को मजबूत करने के बहाने से अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत दिखाते रहे, मगर पार्टी हाईकमान ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर भाजपा के नेता भी मुखर रहते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा कई मामलों में सहआरोपी हैं। इस कारण कांग्रेस के लिए हुड्डा की अनदेखी करना आसान नहीं है।

हुड्डा के पास है नैया पार लगाने का फार्मूला : रविवार को हुड्डा ने बैठक में संकेत भी दिया कि उनके पास विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने का फार्मूला है। पार्टी हाईकमान यदि उन्हें अभी भी संगठन की कमान दे तो वे इस फार्मूले को अपनाकर भाजपा के विजय रथ को रोक सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि हुड्डा समर्थक इस बार हाईकमान की तरफ से भी सिर्फ चार अगस्त तक ही इंतजार करेंगे। इसके बाद वे 18 अगस्त को बड़ा एलान करने के लिए रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यदि रैली से पहले हुड्डा को पार्टी की कमान मिल गई तो रोहतक रैली में प्रियंका गांधी मुख्य वक्ता के रूप में आएंगी और यहीं से पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का श्रीगणेश भी करेगी।

एनएमसी विधेयक में 25 सदस्यीय सलाहकार परिषद के गठन का है प्रावधान

जेएनएन, नई दिल्ली

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) विधेयक एमसीआइ को बदलने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति द्वारा चुने गए 25 सदस्यीय एनएमसी के गठन के लिए शक्ति प्रदान करता है। आयोग के जरिये एक चिकित्सा सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य शामिल होगा। यूजीसी के अध्यक्ष, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड एसेसमेंट काउंसिल के निदेशक और मूल्यांकन परिषद के निदेशक एनएमसी को सलाह देंगे और सिफारिश करेंगे। स्थापना और मान्यता के लिए मेडिकल कॉलेजों को केवल एक बार अनुमति की आवश्यकता होगी। कॉलेज अपने दम पर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा और वे अपने दम पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू कर सकेंगे।

2019 विधेयक में बदलाव : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति की 109वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहला, अलग से होने वाली एक्जिट परीक्षा खत्म कर दी गई है। दूसरा, उस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया है, जिसमें होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को एक ब्रिज कोर्स के बाद एलोपैथी दवा लिखने की अनुमति थी।

16वीं लोकसभा में पहली बार पेश हुआ था विधेयक : लोकसभा में सोमवार को पारित हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) विधेयक को पहली बार 16वीं लोकसभा में पेश किया गया था। कुछ प्रावधानों पर विपक्ष और डॉक्टरों के विरोध के बाद इसे संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 92वीं रिपोर्ट (2016) में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के कामकाज की जांच की और इसकी तीखी आलोचना की। जांच में पता चला था कि एमसीआइ अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता अपने निम्नतम स्तर पर है; चिकित्सा शिक्षा का वर्तमान मॉडल अच्छे स्वास्थ्य पेशेवरों का उत्पादन नहीं कर रहा है, जो देश की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चिकित्सा स्नातकों में सामान्य प्रसव कराने जैसे बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल कार्यों को करने की क्षमता की कमी है।

छग बीज विकास निगम ने दागी कंपनी को दे दिया सप्लाई का काम

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के बीज विकास निगम का नया कारनामा सामने आया है। निगम के अधिकारियों ने दागी कंपनियों को एक बार फिर ठेका दे दिया है। निगम ने फरवरी में तीन कंपनियों त्रिमूर्ति प्लांट सर्विस, वेस्ट बंगाल हाइब्रिड सीड और इंडो यूएस बायोटेक की जमा राशि को जब्त किया था। अब जून में दोबारा इन तीनों कंपनियों को सब्जी के बीज सप्लाई का काम दे दिया गया है।

बीज विकास निगम ने हार्टिकल्चर बीज सप्लाई का काम सात कपंनियों को दिया था। इसमें से तीन कंपनी त्रिमूर्ति प्लांट सर्विस, वेस्ट बंगाल हाइब्रिड सीड और इंडो यूएस बायोटेक के तकनीकी दस्तावेज सही नहीं पाए गए। इसके बाद इन निगम ने इन कंपनियों के रेट कांट्रेक्ट को निरस्त कर दिया था और भुगतान पर रोक लगा दी थी। बीज विकास निगम के तत्कालीन एमडी जनमेजय महोबे ने कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। अब एमडी नरेंद्र दुग्गा ने एक बार फिर इन्हीं कंपनियों को बीज सप्लाई का काम दे दिया। दुग्गा ने बताया कि इन तीनों कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया था। कंपनी शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए उनकी राशि को जब्त किया गया था। ओपन टेंडर के कारण ये कंपनियां एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुई हैं। अगर इन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया होता, तो टेंडर प्रक्रिया से दूर रखा जाता।

अनुच्छेद-370 पर संतों की इच्छा होगी पूरी : भागवत

जागरण संवाददाता, मथुरा

मथुरा के रमणरेती आश्रम में रमणेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक करते संघ प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को देश में संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर संतों की राय ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 व 35 ए खत्म करने की संतों की मांग पर सहमति जताते हुए उन्होंने जल्द ही संतों की इच्छा पूरी होने का संकेत भी दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक सदभाव बैठक के समापन के अगले दिन संघ प्रमुख सोमवार को सबसे पहले मथुरा के ज्ञानगुदड़ी स्थित हंस देवराह बाबा आश्रम पहुंचे। यहां संत हंस देवराह बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद संघ प्रमुख भागवत ने उनके साथ एकांत में आध्यात्मिक चर्चा भी की।

संघ प्रमुख परिक्रमा मार्ग स्थित कृष्णकृपा धाम आश्रम पहुंचे। यहां महामंडलेश्वर गीता मनीषी संत ज्ञानानंद के सानिध्य में तीर्थनगरी के अनेक संतों ने संघ प्रमुख के साथ राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर चर्चा की। संत ज्ञानानंद ने बताया कि आश्रम पहुंचे संघ प्रमुख ने संतों की कश्मीर से अनुच्छेद-370 तथा 35 ए हटाने की मांग पर अपनी सहमति जताई। कहा कि जल्द ही संतों की इच्छा के अनुसार सरकार के कार्य देखने को मिलेंगे। संत ज्ञानानंद ने बताया कि संघ प्रमुख ने संतों के साथ देश में शिक्षा नीति को संस्कार युक्त बनाने पर उनकी राय जानी और हरिद्वार कुंभ को और अधिक सुसंस्कृत बनाने पर भी चर्चा की।

इससे पूर्व संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों के साथ प्रसाद ग्रहण किया और संत ज्ञानानंद के साथ करीब आधा घंटे एकांत में चर्चा भी की। संघ प्रमुख सोमवार सुबह महावन स्थित रमणरेती आश्रम पहुंचे। यहां रमणेश्वर महादेव मंदिर में भागवत ने भोलेनाथ का महाभिषेक कर पूजा-अर्चना की।

35ए पर महबूबा ने फारूक से सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-35ए पर वैसे तो कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों की एक ही विचारधारा है, लेकिन ये दल कभी भी इस मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर नहीं आए। एक दिन पहले ही अनुच्छेद-35ए के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को हाथ लगाने के बराबर बताने वाली पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब इस मुद्दे पर और मुखर हो गई हैं। सोमवार को महबूबा ने कहा कि कश्मीर में हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं, उससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब से सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। समय की जरूरत है कि सभी एक साथ आएं और एकजुट होकर सरकार को जवाब दें।

महबूबा मुफ्ती ने गत रविवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर अनुच्छेद 35ए के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर केंद्र सरकार को चेताया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर भी तंज कसा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और केंद्र को उस पर विश्वास करना चाहिए। महबूबा ने कहा था कि अनुच्छेद 35ए पर छेड़छाड़ का किसी को भी अधिकार नहीं है। पीडीपी की स्थापना ही राज्य के विशेषाधिकार के संरक्षण को लेकर हुई थी और जब तक उनकी जान है, वह संघर्ष करती रहेंगी।

उमर बोले, पहले केंद्र की मंशा का पता चले : नेशनल कांफ्रेंस के उपप्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के हालात पर चर्चा करने के लिए दूसरे दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाने से पहले यह समझने का प्रयास करना होगा कि केंद्र सरकार की कश्मीर को लेकर क्या मंशा है। इस समय कश्मीर के हालात को केंद्र सरकार किस तरह से देख रही है। नेशनल काफ्रेंस का ध्यान फिलहाल इसी पर है। यह बात उमर ने एक ट्वीट कर कही।

डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से मांगा समय : नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ पार्टी नेता हसनैन मसूदी और मुहम्मद अकबर लोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है।

अब एसएसपी श्रीनगर का पत्र हुआ वायरल, मस्जिदों की मांगी जानकारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- कश्मीर में अनुच्छे- 35ए को लेकर चर्चाएं और हलचल तेज
- राजनीति बढ़ते देख एसएसपी ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया

अनुच्छेद 35ए को लेकर जारी चर्चाओं के बीच अब श्रीनगर के एसएसपी का पत्र वायरल होने से कश्मीर में फिर हलचल तेज हो गई है। इस पत्र में एसएसपी ने अपने पांच जोनल एसपी को अपने-अपने क्षेत्र की मस्जिदों और उनकी प्रबंधक कमेटियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा है। पत्र से कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ते देख एसएसपी ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र में एसएसपी ने अपने आदेश में कहा कि तत्काल प्रभाव से सभी एसपी अपने-अपने क्षेत्र की मस्जिदों और उनकी प्रबंधक कमेटियों के बारे में जानकारी दें, ताकि उन्हें उच्चाधिकारियों के पास भेजा जा सके। इसके बाद कश्मीर में फिर चर्चा शुरू हो गई कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 35-ए को खत्म करने के लिए ही ऐसे आदेश जारी कर रही है। श्रीनगर के एसएसपी डॉ. हसीब मुगल ने कहा कि मस्जिदों की जानकारी मांगना पुलिस की सामान्य प्रक्रिया है। डाटा अपडेट करने के लिए ही जानकारी मांगी गई है। पुलिस के पास मस्जिदों, गुरुद्वारों सहित सभी धार्मिक स्थलों का डाटा मौजूद है।

चार दिन में बन गया बड़ा मुद्दा, सियासत गरमाई : कश्मीर में चार दिन में अनुच्छेद 35ए बड़ा मुद्दा बन गया और एक के बाद एक कई पत्र वायरल होने से सियासत चरम पर पहुंच गई।

26 जुलाई : अर्धसैनिकबलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने के केंद्र के फैसले से कश्मीर में सियायत शुरू हुई। इसी बीच घाटी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दौरे से 35ए की चर्चाओं को और हवा मिली।

27 जुलाई : जम्मू कश्मीर शसस्त्र पुलिस बल नियंत्रक कक्ष के एसएसपी की ओर से राज्य के सभी जिला एसएसपी को दंगाइयों से निपटने के लिए सभी साजो-सामान पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश जारी हुए। इसके साथ ही कश्मीर में राजनीति भी तेज हो गई। इसे भी 35ए से जोड़कर देखा गया।

28 जुलाई : रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र में कहा गया कि अगले तीन-चार महीने में कश्मीर में हालात खराब हो सकते हैं। उन्होंने स्टाफ को चार महीने के लिए राशन एकत्र करने, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने को कहा था। बाद में रेलवे को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी कि इस पत्र का कोई आधार नहीं है।

29 जुलाई : अब एसएसपी श्रीनगर का मस्जिदों और उनकी प्रबंधक कमेटियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने का पत्र वायरल हुआ है।

कश्मीर के हालात पर पत्र लिखने वाले अधिकारी का तबादला

कश्मीर के हालात खराब होने का पत्र लिखने वाले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। फोर्स के डीजी अरुण कुमार ने असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर बड़गाम सुदेश नुग्याल का तबादला किया है। मुरादाबाद सीनियर डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर संदीप रविवंशी को श्रीनगर में नियुक्त किया गया है। वहीं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आइजी को श्रीनगर में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर बड़गाम सुदेश नुग्याल ने एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि आने वाले तीन से चार महीने में कश्मीर में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। चार महीने का राशन एडवांस में खरीद लें। सात दिनों के लिए पानी स्टोर करने, स्टाफ को पूरे सामान सहित पिट्ठू बैग तैयार रखने, गाड़ियों में पेट्रोल भराकर उन्हें गैराज में पार्क करने, रेलवे के पास भीड़ को न आने देने सहित अपने परिजनों को कश्मीर में न ठहरने देने सहित कई बातें लिखी गई थी।

पहल

नई राज्यपाल आनंदीबेन के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान राज्यपाल भी रहे मौजूद, ऐसा पहली बार हुआ है

राजभवन छोड़ने से पहले राम नाईक ने तोड़ी एक और परंपरा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

यूं तो संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद के लिए 33 शपथ ग्रहण समारोह पहले हो चुके हैं, लेकिन सोमवार को 34वें राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल का शपथ ग्रहण समारोह पहले वालों से कुछ अलग ही था। पहले की परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार ऐसा हुआ कि नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान राज्यपाल भी मौजूद रहे।

दरअसल, अब तक यही परंपरा रही है कि नए राज्यपाल के आने से पहले ही निवर्तमान राज्यपाल राजभवन को छोड़ देते थे। राम नाईक ने इस रूढ़ि को ठीक न मानते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कोई परंपरा नहीं है तो यहां भी इसे बदलना है। ऐसे में भले ही नाईक का पांच वर्ष का कार्यकाल 22 जुलाई को पूरा हो चुका था और उससे पहले 20 जुलाई को ही आनंदीबेन को यहां का राज्यपाल बनाने का आदेश आ गया था, लेकिन नाईक ने राजभवन नहीं छोड़ा। नियमानुसार इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पहले से चली आ रही परंपरा टूटी।

सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल रहते राम नाईक, आनंदीबेन के साथ गांधी सभागार में पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही वहां रखीं तीन कुर्सियों में नाईक बीच वाली पर बैठ गए। नाईक के एक तरफ मुख्य न्यायाधीश और दूसरी तरफ वाली कुर्सी पर आनंदीबेन बैठीं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाए जाने के बाद नाईक अपनी कुर्सी से उठकर किनारे वाली उस कुर्सी पर आ गए जहां आनंदीबेन बैठी थीं। शपथ और हस्ताक्षर के बाद आनंदीबेन बीच वाली कुर्सी पर बैठ गईं। राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह के समाप्त होने के बाद नाईक, आनंदीबेन को लेकर राजभवन स्थित राज्यपाल के कार्यालय में भी पहुंचे। आनंदीबेन के राज्यपाल की कुर्सी संभालने के बाद नाईक उन्हें लेकर राजभवन के प्रथम तल पर पहुंचे। नाईक ने आनंदीबेन को दोपहर का भोज (लंच) कराया और उसके बाद खुद परिवार के साथ राजभवन से मुंबई के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए।

गौरतलब है कि राज्यपाल के तौर पर अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान राम नाईक ने कई और परंपराओं को भी तोड़ा और बहुत कुछ नया शुरू किया। नाईक ने राज्यपाल को महामहिम कहने के बजाय माननीय कहलाने की व्यवस्था भी लागू की।

लखनऊ में सोमवार को राजभवन में आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल पद की शपथ दिलाते इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। साथ में उपस्थित निवर्तमान राज्यपाल राम नाईक। जागरण